

नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर साधा निशाना संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाकर रखा नहीं की जा रही नियुक्ति : बाबूलाल मरांडी

संविधान से नहीं ‘मुखेर कानून’ से चल रही राज्य सरकार

आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा। श्री मरांडी प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य की ऐसी सारी संवैधानिक संस्थाएं जो राज्य सरकार के काम काज, गड़बड़ियों, भ्रष्टाचार पर नजर रखती हैं। जनता की शिकायत पर सुनवाई और कार्रवाई करती है उसको सरकार ने पंगु बनाकर रखा है।

उन्होंने कहा कि राज्य में लोकयुक्त, महिला आयोग, सूचना आयोग, उपभोक्ता फोरम जैसी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में वर्षों से अध्यक्ष/ सदस्य के पद खाली हैं। कहीं अध्यक्ष हैं तो सदस्य नहीं, कहीं न अध्यक्ष हैं न सदस्य। संस्थान सिर्फ नाममात्र का रह गया है।

कहा कि ये संवैधानिक संस्थाएं जनता को न्याय दिलाने में सहायक होती हैं, सरकार को पारदर्शी और जवाबदेह बनाती हैं।



लेकिन आज इनका पंगु रहना लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर रही है।

कहा कि राज्य सरकार नेता प्रतिपक्ष नहीं होने का बहाना बनाती थी जबकि सच्चाई है कि भाजपा ने समय पर नेता चुनकर दिया है। पिछले टर्म में दो बार नेता का चयन किया गया लेकिन परिणाम शून्य रहा। आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है लेकिन हेमंत सरकार की नियत

साफ नहीं। यह सरकार अपनी नाकामियों, विफलताओं, भ्रष्टाचार को उजागर नहीं होने देना चाहती। लोग शिकायत करेंगे तो मामला संवैधानिक जांच के घेरे में आयेगा। सूचनाएं मांगे जाने पर उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी। राज्य सरकार इससे बचना चाहती है। कहा कि सूचना आयुक्त का पद खाली है, महिला आयोग में 2020 से ही अध्यक्ष और सदस्य का पद खाली है, जिसमें 5000 से

अधिक मामले लंबित हैं, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा। यहां कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल रहा। एक सफाई कर्मी की मौत भी हो चुकी है। उपभोक्ता फोरम में दर्जन भर जिले अध्यक्ष और सदस्य विहीन हैं। कहा कि लोकयुक्त के नहीं रहने से न तो कोई शिकायत दर्ज हो रही, न कोई भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई हो रही। जबकि लोकयुक्त जैसी स्वतंत्र संस्था

राज्य में काम करेगी तो मंत्री, विधायक बड़े पदाधिकारी, यहां तक कि एसीबी के विरुद्ध भी गलत और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई और जांच की शिकायत की जा सकेगी। जो आज नहीं हो पा रहा।

कहा कि हाइकोर्ट के निर्देशों के बावजूद इन पदों को नहीं भरा का रहा है। इससे स्पष्ट है कि यह सरकार जानबूझकर संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां नहीं करना चाहती है। ताकि किसी भी प्रकार के गलत काम के विरुद्ध किसी बड़ी मछली के खिलाफ स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच और दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो। कहा कि राज्य सरकार संवैधानिक तरीके से नहीं बल्कि ‘मुखेर कानून’ चलाना चाहती है। श्री मरांडी ने मांग की कि अखिलब सूचना आयुक्त, महिला आयोग, लोकयुक्त जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति की जाये। प्रेसवार्ता में मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा उपस्थित थे।

आइएएस विनय चौबे की जांच करेगी डाक्टरों की टीम, नेफ्रोलांजी विभाग को भेजी गयी रिपोर्ट

आइएएस विनय चौबे को हाइ ब्लड प्रेशर और किडनी से जुड़ी समस्याएं
रिस्म में विनय चौबे की तबीयत फिलहाल स्थिर



विनय चौबे की तबीयत फिलहाल ठीक है। उनकी जांच के लिए रिस्म में डॉक्टरों की एक टीम बनायी गयी है। इस टीम में मेडिसीन, किडनी और हार्ट के विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। जिनमें- डॉ. ऋषि तुहिन गुड़िया, डॉ. अजीत दुंगुडुंग, डॉ. प्रज्ञा पंत और डॉ. मृणाल कुंज शामिल हैं। इससे पहले गुरुवार की रात आइएएस चौबे की पत्नी खाना लेकर उनसे मिलने रिस्म गयी थीं। लेकिन वहां चौबे की पत्नी को उनसे मिलने नहीं दिया गया। खबर है कि विनय

चौबे के लिए लाया गया घर का खाना वापस करवा दिया गया। इसके बाद विनय चौबे की पत्नी लौट गयीं। हालांकि उन्होंने मीडिया को कोई बयान नहीं दिया। कोर्ट के दिशा-निर्देश में मेडिकल बोर्ड की बैठक हुई थी। रिस्म के सीनियर डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने विनय चौबे के इलाज से संबंधित दस्तावेज के आधार पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिस्म में भर्ती करने की अनुशंसा की थी। उन्हें किडनी की गंभीर समस्या है। मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के बाद बिरसा सेंट्रल

एसीबी मुख्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने की बैठक

रांची (आजाद सिपाही)। रांची शराब घोटाले मामले में एसीबी की कार्रवाई तेज हो गयी है। मामले में एसीबी के डीजी और डीजीपी अनुराग गुप्ता एसीबी शुक्रवार को कार्यालय पहुंचे। वह लगभग दो घंटे तक एसीबी कार्यालय में मौजूद रहे। उन्होंने शराब घोटाले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर मामले की जानकारी ली। डीजी एसीबी ने पूरे मामले की जानकारी ली और कई दिशा निर्देश दिये। बता दें कि मामले में एसीबी ने अब तक कार्रवाई करते हुए विनय कुमार चौबे सहित पांच को गिरफ्तार कर चुकी है। एसीबी ने



आइएएस विनय कुमार चौबे, उत्पाद विभाग के अधिकारी गजेंद्र सिंह, जेएसबीसीएल के वर्तमान जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास और तात्कालीन जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार और एजेंसी के लोकल कर्मी वीरज सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है।

बाद उन्हें एसीबी की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को 3 जून तक (14 दिन) न्यायिक हिरासत में भेजा है।

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना : मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो 6 जून तक करें आवेदन

आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। अगर आप झारखंड से हैं और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से ख्वाब पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में घबरायें नहीं। झारखंड सरकार एक ऐसी योजना लायी है, जिसके तहत आप भी विदेश में पढ़कर अपने सपने को साकार कर सकते हैं। सरकार द्वारा ऐसे तमाम होनहार छात्रों के लिए मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना लायी गयी है।



साल 2021 से शुरू इस योजना के तहत अब तक झारखंड के कई छात्र इसका लाभ उठा चुके हैं। शुरुआत में इस योजना के तहत 10 विद्यार्थियों को ही उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जा रहा था। बाद में इसकी संख्या 25 की गयी है। हालांकि सरकार इस योजना के तहत विद्यार्थियों का इंटरव्यू लेकर 25 छात्र-छात्राओं का

छात्रवृत्ति के लिए चयन करेगा। चयनित छात्र-छात्राओं में अनुसूचित जनजाति के 10, अनुसूचित जाति के पांच, पिछड़ा वर्ग के 7 और अल्पसंख्यक समुदाय के 3 विद्यार्थी शामिल रहेंगे। इन सभी विद्यार्थियों को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्डन आयरलैंड के लिए

आवेदन में समस्या आने पर करें वाट्सअप पर संपर्क : अजय नाथ झा

कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने जानकारी देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को इससे संबंधित कोई जानकारी या परेशानी हो तो जारी वाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। जिसके माध्यम से विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि 29 दिसंबर 2020 को हेमंत सरकार के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की

थी। योजना के तहत 2021 में छह छात्रों को चयन किया गया था और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा गया था। जिसके बाद 2022 में छात्र-छात्राओं की संख्या को बढ़ाकर 25 किया गया। उसी के तहत इस साल भी प्रक्रिया शुरू की गयी है। योजना के तहत अधिकतम 35 वर्ष की उम्र के एससी, एसटी और ओबीसी विद्यार्थियों को 31 विषयों में मास्टर्स और एमफिल की डिग्री लेने के लिए विदेश जाने का मौका राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है।

चयनित विश्वविद्यालय या संस्थानों में उच्च स्तरीय शिक्षा की

राज्य सरकार द्वारा सुविधा प्रदान की जायेगी।

भाजपा के आरोप बेबुनियाद, भ्रामक और तथ्यहीन : विनोद कुमार पांडेय



आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी द्वारा झारखंड सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने के आरोप पर सतारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने पलटवार किया है। पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि मरांडी का बयान पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन है। पांडेय ने कहा कि मरांडी यह भूल रहे हैं कि पिछली सरकार में चार वर्षों तक भाजपा ने खुद नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किया, जिससे कई संवैधानिक नियुक्तियां लटकी रहीं। भाजपा ने ऐसा जानबूझ कर किया। अपने इस कृत्य का जवाब भाजपा देगी क्या? पहले उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार संस्थाओं को सक्रिय और प्रभावी बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है, लेकिन भाजपा सिर्फ राजनीतिक आरोप लगाने में व्यस्त है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का मकसद सिर्फ भ्रम फैलाना और जनता को गुमराह करना है। हेमंत सरकार की कल्याण, निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर में मील

का पत्थर साबित करते हुए ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। हर वर्ग के लिए जरूरी योजनाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारा जा रहा है। लेकिन, भाजपा राज्य के लोगों का हक मारने के लिए केंद्र सरकार का दुरुपयोग कर रही है। झारखंड की लाभुक योजनाओं, विकास योजनाओं के मद में जानबूझ कर फंड देने में देरी की जा रही है। लेकिन, राज्य की जनता ये सब समझ चुकी है और यही कारण है कि पिछले चुनाव में प्रचंड बहुमत देकर हेमंत सरकार को सत्ता में वापस ले आयी है।

विनोद पांडेय ने कहा कि हेमंत सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर काम कर रही है। सरकार सभी संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए चरणबद्ध रूप से कदम उठा रही है और नियुक्तियों की प्रक्रिया भी चल रही है। झामुमो नेता ने भाजपा से पहले अपनी भूमिका की जवाबदेही तय करने की मांग की और कहा कि झुठे आरोपों के जरिए सरकार की छवि खराब करने की साजिश सफल नहीं होगी।

डीपीएस रांची की प्राचार्या के रूप में डॉ जया चौहान ने कार्यभार संभाला

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। डॉ जया चौहान ने औपचारिक रूप से दिल्ली पब्लिक स्कूल, रांची की प्राचार्या के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति हाल ही में दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी, नयी दिल्ली द्वारा की गयी। जिन्होंने उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता, विशिष्ट सेवा और सिद्ध नेतृत्व कौशल को मान्यता दी है। लगभग दो दशकों तक डीपीएस रांची में वरिष्ठ अंग्रेजी शिक्षिका के रूप में सेवा देने वाली डॉ चौहान स्कूल की संस्कृति और मूल्यों से भलीभांति परिचित हैं। संस्था के साथ उनका गहरा जुड़ाव और वर्षों में उनके द्वारा किये गये असाधारण योगदान ने उन्हें व्यापक सम्मान और प्रशंसा दिलायी है। शैक्षणिक प्रभारी, समयसारणी प्रभारी और गतिविधि प्रभारी जैसे विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने अपनी बहुआयामी क्षमताओं



और शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है।

डीपीएस रांची में उनके सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक है डीपीएस रांची को सैट केंद्र

बनाना जिसने विद्यालय की शैक्षणिक प्रतिष्ठा को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया। उनकी नवोन्मेषी सोच और दूरदर्शी दृष्टिकोण ने पारंपरिक शिक्षण और प्रशासन की सीमाओं को लगातार चुनौती दी है।

डीपीएस रांची में वापसी से पूर्व, डॉ चौहान डीपीएस राउरकेला की प्राचार्या थीं, जहां उनके संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली नेतृत्व में स्कूल ने उल्लेखनीय शैक्षणिक प्रगति और संस्थागत उपलब्धियां हासिल कीं। उनके नेतृत्व में डीपीएस राउरकेला भी एक मान्यता प्राप्त सैट केंद्र बना, और विद्यालय में अनुशासन व शैक्षणिक परिणामों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण और छात्र विकास के प्रति गहरे समर्पण के साथ, उनसे डीपीएस रांची में एक नये युग की शुरुआत की उम्मीद की जा रही है।

11वीं-13वीं जेपीएससी : डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन-इंटरव्यू शेड्यूल जारी

आज से डाउनलोड होगा कॉल लेटर

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने 11वीं और 13वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सफल 864 अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया है।



जरूरी दस्तावेज न भूलें

जेपीएससी ने सभी चयनित उम्मीदवारों से अपील की है कि वे इंटरव्यू और वेरिफिकेशन के समय अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित हों।

अभ्यर्थी को कॉल लेटर डाउनलोड करने में दिक्कत आती है, तो हेल्पलाइन नंबर 9431301419 या 9431301636 पर सुबह 11

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू की तारीखें

- दस्तावेज सत्यापन : 9 जून से 22 जून 2025 तक
- समय : सुबह 10 बजे से
- इंटरव्यू : 10 जून से 23 जून 2025 तक
- समय : सुबह 9.30 बजे से
- स्थान : जेपीएससी कार्यालय, रांची
- अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के दिन सुबह 9:30 बजे तक रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।
- कॉल लेटर डाउनलोड करने की तिथि और तरीका

बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

फिर कोरोना की दस्तक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना महामारी की पहली लहर जनवरी 2020 से फरवरी 2021 तक रही। इस दौरान कोरोना के 1.08 करोड़ मामले सामने आये और औसतन रोजाना 412 मौतों के हिसाब से लगभग 1.55 लाख लोगों की मौतें हुईं। कोरोना की दूसरी लहर (मार्च, 2021 से मई, 2021) में 1.69 लाख मौतें तथा तीसरी लहर (दिसंबर, 2021 से फरवरी, 2022) के दौरान 50.05 लाख नये मामले दर्ज किये गये और 10,465 मौतें हुईं और अब एक बार फिर भारत सहित दक्षिण एशिया के कई देशों में कोरोना की नयी लहर (वेरिएंट) का खतरा मंडराने लगा है। हांगकांग और सिंगापुर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। जहां हांगकांग में अभी तक सामने आये कोरोना के 81 मामलों में 30 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं सिंगापुर में 1 मई तक कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ कर 14,200 हो गयी। वहां 1 से 19 मई के बीच इसके 3,000 नये मरीज सामने आये हैं। सिंगापुर व हांगकांग के बाद चीन और थाईलैंड में भी इसके मामले बढ़ने लगे हैं तथा अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यह महामारी एक बार फिर गंभीर रूप ले सकती है और इसका असर एशिया के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है। हांगकांग में संक्रामक रोगों के स्वास्थ्य अधिकारी अलबर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अतः सांस की तकलीफ वाले

हांगकांग और सिंगापुर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। जहां हांगकांग में अभी तक सामने आये कोरोना के 81 मामलों में 30 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं सिंगापुर में 1 मई तक कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ कर 14,200 हो गयी।

रोगियों के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने की आशंका इस वर्ष बहुत अधिक बढ़ सकती है, जिसे लेकर भारत में भी चिंता पैदा हो गयी है। हालाँकि भारत में अभी कोरोना की कोई बड़ी लहर दिखायी तो नहीं दे रही है, परंतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 1 जनवरी से 19 मई तक देश में कोरोना के 257 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से अकेले मुंबई में ही 53 मामले सामने आये हैं तथा मुंबई के केशएम अस्पताल में 19 मई को 2 कोरोना पीड़ितों की मौत भी हो चुकी है। हालाँकि सरकार स्थिति को नियंत्रण में बता रही है, लेकिन मुंबई में डाक्टरों ने कोरोना के और भी हल्के लक्षणों वाले मामले देखे हैं। इस बार संक्रमण के लिए ओमिक्रोन के नये वेरिएंट जेएन.1 तथा उसके साथ वेरिएंट्स एलएफ 7 और एनबी 1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। जेएन.1 वेरिएंट काफी तेजी से फैलता है। इंग्लैंड के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के जेएन.1 सब-वेरिएंट से संक्रमित लोगों ने कुछ संकेत बताये हैं, जिनमें गले में खराश, नींद न आने की समस्या, एंजाइटी, नाक का बहना, खांसी, सिरदर्द, कमजोरी या थकान, मांसपेशियों में दर्द आदि शामिल हैं।

अभिमतआजाद सिपाही

कर्नल सोफिया कुरैशी होने का महत्व

जूलियो रिबैरो

मध्य प्रदेश की भाजपा शासित सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री विजय शाह ने अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असमंजस में डाल दिया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद देश की प्रतिक्रिया को बेहतर ढंग से संभालने के लिए मोदी की प्रशंसा उनके कई आलोचकों द्वारा की गयी थी, जिनमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी शामिल थे। यह बात उनके आलोचकों तथा देश के विभिन्न भागों से आने वाले आम नागरिकों द्वारा सर्वत्र स्वीकार की गयी कि मोदी द्वारा सशस्त्र सेना प्रवक्ताओं का चयन, जो प्रतिदिन प्रेस तथा राष्ट्र को भारत के जवाब के बारे में जानकारी देंगे, अत्यंत शानदार था।
दो महिला अधिकारियों को चुना गया, सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली सिग्नल्स रैंजीमेंट की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायु सेना के हैलीकॉप्टर विंग से विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन दोनों सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए न केवल महिलाओं को चुना गया, बल्कि इनमें से एक मुस्लिम को भी चुना गया, जो कि एक मास्टरस्ट्रोक था। यह दुविधा तब पैदा हुई, जब मंत्री विजय शाह ने कर्नल कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया!

मोदी जी ने अपने दिमाग में अपने ही घर में बड़ी संख्या में जन्मजात मुस्लिम द्वेषियों की मौजूदगी के लिए कोई जगह नहीं बनायी थी, जिनमें से एक हिंदी पट्टी के एक महत्वपूर्ण राज्य में उनकी डबल इंजन सरकार में मंत्री भी है। जब विपक्षी दलों, विशेष कर कांग्रेस ने विरोध में आवाज उठायी तथा कई नागरिकों ने भी इसका समर्थन किया, जिन्होंने महत्वपूर्ण समय में मोदी के नेतृत्व के गुणों की सराहना करना शुरू

कोल्हान की खबरें

गैंगरेप मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

आजाद सिपाही संवाददाता
जमशेदपुर। शहर के सोनारी थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आयी है। जहां द्यूशन के लिए निकली एक युवती को पहले बहला फुसलाकर जबली पार्क ले गया और फिर एक निर्माणाधीन घर में उसके साथ दोनो युवकों ने गैंगरेप किया। घटना के बाद आरोपियों ने युवती को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने परिजनों के साथ मिलकर सोनारी थाना में शिकायत दर्ज करवायी। शुक्रवार को मामले की गंभीरता को देखते हुए सोनारी पुलिस ने तत्परता दिखायी और महज 10 से 12 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

आरटीआइ कार्यकर्ता संघ की बैठक, धमकी देनेवालों पर कार्रवाई की मांग

जमशेदपुर (आजाद सिपाही)। आरटीआइ कार्यकर्ता संघ की एक उच्चस्तरीय आपात कालीन बैठक साकची स्थित बाल मजदूर सेवा संस्थान, (पुराना कोर्ट परिसर) में संघ के उपाध्यक्ष सदन कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। शुक्रवार को आयोजित बैठक में संघ के केन्द्रीय महासचिव कीर्तिवास मंडल को फोन पर दी गयी धमकी और अब तक प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर चिंता जतायी। आशंका जताई जा रही है धमकी देनेवाले शख्स का संबंध पोर्टका प्रखंड कार्यालय से हो सकता है, क्योंकि उसने धमकी में मांगी गयी सूचना का सीधा उल्लेख किया है। समिति ने मांग की जिला प्रशासन इस मामले में पोर्टका प्रखंड कार्यालय की सल्लिप्तता की जांच अवश्य कराये। बैठक में निर्णय लिया गया आगामी 27 मई को आरटीआइ कार्यकर्ता संघ का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी और डीसी से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपेगी।



पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद देश की प्रतिक्रिया को बेहतर ढंग से संभालने के लिए मोदी की प्रशंसा उनके कई आलोचकों द्वारा की गयी थी, जिनमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी शामिल थे। यह बात उनके आलोचकों तथा देश के विभिन्न भागों से आनेवाले आम नागरिकों द्वारा सर्वत्र स्वीकार की गयी कि मोदी द्वारा सशस्त्र सेना प्रवक्ताओं का चयन, जो प्रतिदिन प्रेस तथा राष्ट्र को भारत के जवाब के बारे में जानकारी देंगे, अत्यंत शानदार था।



मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने नागरिकों की आवाज पर ध्यान देते हुए स्थानीय पुलिस को मंत्री के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है। वास्तव में, पार्टी को नुकसान को सीमित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी।

ही किया था, तभी विजय शाह पार्टी को बिगाड़ने के लिए सामने आ गये। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने नागरिकों की आवाज पर ध्यान देते हुए स्थानीय पुलिस को मंत्री के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है। वास्तव में, पार्टी को नुकसान को सीमित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह पार्टी सदमे में है और अपने विश्वस्त समर्थकों के एक बड़े वर्ग को नाराज करने में असमर्थ है, जो चाहते हैं कि सरकार मुसलमानों को लाड़-प्यार देना बंद कर दे, भले ही वह मुसलमान महिला हो और एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हो, जिसकी समाचार चैनलों पर प्रतिदिन उपस्थिति ने पूरे देश, विशेष कर

महिलाओं को उत्साहित कर दिया है। भाजपा ने हमेशा कांग्रेस पर चुनावी लाभ के लिए मुसलमानों को लाड़-प्यार देने का आरोप लगाया था। एकमात्र लाड़-प्यार जिसका उसे दोषी पाया जा सकता था, वह था मुस्लिम धार्मिक प्रतिष्ठानों को। उन मामलों में लाड़-प्यार देना जो राज्य से संबंधित नहीं थे।

धर्म द्वारा निर्धारित कानून, जिसके तहत वृद्धा शाह बानो के पास इतना अल्प धन बचा था कि वह कुछ दिनों के बाद भूख से मर सकती थी, को न्यायालय द्वारा, बिल्कुल सही ढंग से, पलट दिया गया। लेकिन, राजीव गांधी को उस समय बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा जब उन्होंने शाह बानो मानवाधिकार मामले में अदालत के फैसले को नकारने के लिए संसद में अपनी पार्टी का समर्थन

हासिल कर लिया।

विजय शाह ने सरकार द्वारा एक मुस्लिम महिला अधिकारी को प्रवक्ता के रूप में चुनने को एक तरह का लाड़-प्यार समझ लिया होगा। संभवतः यही कारण है कि उन्होंने यह घृणित टिप्पणी की। और विजय शाह इस विचारधारा के एकमात्र प्रतिनिधि नहीं हैं। देश के कोने-कोने में हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग है, जो मुसलमानों के प्रति गहरी अविश्वास का भावना रखता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है, जो भाजपा ने बनायी हो। पिछले 10 या 11 वर्षों में यह अविश्वास आजादी से पहले भी मौजूद था, लेकिन 2014 तक सुप्त रहा। अब यह खुले तौर पर व्यक्त हो रहा है, लेकिन यह तब भी वास्तविकता थी जब मैं 82 से 90 साल पहले, यानी 1936 से 1944 तक,

कोल्हान की खबरें

सड़क हादसे में दो युवक घायल



पत्रकारों और पुलिस की तत्परता से घायलों को भेजा गया अस्पताल

पुलिस ने भाग रही कार को किया जब्त

आजाद सिपाही संवाददाता

सरायकेला। सरायकेला टाटा मुख्य सड़क पर बीते देर रात कार के चपेट में आने से दो युवक बुरी तरह घायल होगये। मौके पर सड़क से गुजर रहे पत्रकारों की टीम ने पुलिस को सूचना की। साथ ही मानवता का मिसाल पेश करते हुए घायलों को तत्काल एंबुलेंस के सहारे इलाज के लिए अस्पताल भेजबाया। सड़क दुर्घटना में पत्रकारिता की सजगता और पुलिस की तत्परता ने दो दोनों घायलों को समय पर बचा लिया।टाा प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां के पत्रकारों की सूचना पर पुलिस ने न केवल समय पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, बल्कि हादसे के बाद फरार हो रही कार को भी जन्म कर लिया। निवर्तमान अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने बताया घटना देर रात 11:30 बजे की है। कांड्रा थाना क्षेत्र के शेन इंटरनेशनल स्कूल के पास एक तेज रफ्तार काले रंग की कार ने पल्सर बाइक (नं. खए850359-2032) को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार तीन युवकों में से दो गंभीर रूप से घायल होकर खून से लथपथ सड़क पर पड़े तड़प रहे थे। वहां से गुजरने के दौरान स्थानीय लोग उनकी मदद करने से कतराते दिखे।हसी बीच सरायकेला प्रेस क्लब के संरक्षक संतोष कुमार,

प्रशंसा के पात्र बने पत्रकार और पुलिस
इस घटना में प्रेस क्लब के पत्रकारों और पुलिस प्रशासन की तत्परता से यह साबित हुआ सामाजिक जिम्मेदारी और समय पर की गयी कार्रवाई किसी का भी जान बचा सकती हैं। एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने पत्रकारों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा ऐसी सजगता समाज के लिए प्रेरणादायक है।

निवर्तमान अध्यक्ष मनमोहन सिंह, सुमित सिंह, विश्वरूप पांडा, विपिन वाणेंय, के दुर्गा राव और सरायकेला थाना क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया। एंबुलेंस के पहुंचते ही पत्रकारों की सहायता से घायल युवकों को इलाज के लिए टीएमएच भेजा गया। मौके पर गम्हरिया थाना प्रभारी कुणाल कुमार ने टीम के साथ दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और क्षतिग्रस्त बाइक को हटवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के बाद कार सरायकेला की ओर भाग निकली थी। पुलिस ने नाकेबंदी कर कार को पकड़ लिया। दुर्घटना में घायल युवकों की पहचान बिरबांस निवासी लव कालिंदी और भोलाडीह निवासी प्रदीप कुंभकार के रूप में हुई। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है।

द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां के सत्र 2025-27 के लिए चुनाव की तैयारी पूरी, मतदान आज



सरायकेला (आजाद सिपाही)। सरायकेला-खरसावां जिला के एकमात्र मान्यता प्राप्त पत्रकार संगठन द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला-खरसावां के सत्र 2025-27 के लिए होने वाले चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। शुक्रवार को चुनाव पर्यवेक्षक संतोष कुमार पर संतोष के दुर्गा राव ने मतदान स्थल का निरीक्षण कर प्रशासनिक तैयारियों पर संपोष जताया। मुख्य पर्यवेक्षक संतोष कुमार ने बताया सरायकेला सूचना भवन में शनिवार (24 मई) को चुनाव होना है। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू होगा और सभी सदस्यों को सुबह 9 बजे तक पहचान पत्र के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया सभी पत्रकारों को शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से चुनाव में भाग लेने की अपील की है। फिलहाल चुनाव को लेकर सदस्यों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।

गृहरक्षा वाहिनी लोक सेवक संघ प्रतिनिधि मंडल ने होमगार्ड एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर सांसद को सौंपा स्मार पत्र



जमशेदपुर (आजाद सिपाही)। गृहरक्षा वाहिनी लोक सेवक संघ जिला शाखा पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के एक प्रतिनिधिमंडल ने सांसद विद्युत वरण महतो से उनके बिष्टुपर स्थित आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कर होमगार्ड एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर एक स्मारपत्र सौंपा। साथ ही डीसी पूर्वी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित आवेदन पत्र भी भेजा गया।प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से अपील की होमगार्ड एक्ट में शामिल स्वयंसेवी शब्द को हटाया जाये और होमगार्ड जवानों को राज्य अथवा केन्द्रीय कर्मी का दर्जा दिया जाये। ज्ञापन के माध्यम से कमल शर्मा ने बताया गया वर्तमान में गृह रक्षक वर्ग सरकारी उपेक्षा और विभागीय तिरस्कार का शिकार है। स्मारपत्र में यह भी उल्लेख किया गया वर्ष 2023 में सांसद विद्युत वरण महतो और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मांग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को अनुरांसा की थी। उसके बावजूद अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिबौलियों के माध्यम से जवानों का शोषण हो रहा है। जवान हर विषम परिस्थिति में पुलिस बल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं, लेकिन उनकी शोषणित मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह करते हुए इस मुद्दे को संवेदनशीलता से संज्ञान में लेते हुए होमगार्ड एक्ट में आवश्यक संशोधन करने का आग्रह किया। ताकि जवानों का जीवन स्तर सुधरे और वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष परितोष महतो, उपाध्यक्ष तपन चंद्र महतो, जिला सचिव भगान हासदा, संगठन सचिव दुला महती, प्रवक्ता लखन किस्कु सहित कई गृह रक्षक उपस्थित रहे।



